

भारत सरकार  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1341  
उत्तर देने की तारीख: 25.11.2019

नई शिक्षा नीति

1341. डॉ. अमर सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुल बजट में से शिक्षा के लिए केवल तीन प्रतिशत बजट ही आवंटित किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या एक ओर सरकार नई शिक्षा नीति तथा एक अनुसंधान निधि एवं कौशल विकास और एक नई तथा सुधार की गई उच्च शिक्षा विनियामक कार्यान्वित कर रही है तथा दूसरी ओर यह विद्यालयी शिक्षा पर खामोश है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री  
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 94853.64 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। भारत में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी का लगभग 4.38% (बजटीय व्यय का विश्लेषण 2016-17) के आसपास है; वर्तमान में, कुल सरकारी खर्च का लगभग 10% शिक्षा (आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18) की ओर जाता है।

सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया में है जिसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा सहित स्कूल व उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों और उप-क्षेत्रों पर कई सुझाव और इनपुट प्राप्त हुए हैं। डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने वाली समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रारूप एनईपी 2019, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट और साथ ही [innovate.mygov.in](http://innovate.mygov.in) प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था, पर भारत सरकार के मंत्रालयों

और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से बड़ी संख्या में सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।  
वर्तमान में, मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

\*\*\*\*\*